राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

श्रीमती वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

द्वारा

राजस्थान विधान सभा के समक्ष
वर्ष 2014-2015 के
बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत वक्तव्य

20 फरवरी, 2014

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 2014–15 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण और वर्ष 2013–14 के संशोधित अनुमान सभा पटल पर रख रही हूँ।

2. राज्य में नवम्बर, 2013 में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों में राज्य की जनता ने राज्य के तीव्र विकास और राज्य में सुराज लाने हेतु हमारी नीतियों, संकल्पों और प्राथमिकताओं में गहरा विश्वास व्यक्त करते हुए हमें ऐतिहासिक जनादेश प्रदान किया है। हमारे पिछले शासनकाल की तरह, इस बार भी हम कुशल वित्तीय प्रबंधन और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतया कृत संकल्प हैं। राज्य में सुराज लाना हमारी प्रतिबद्धता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास और रोजगार सृजित करने वाली आर्थिक नीतियों के माध्यम से राजस्थान को एक विकसित

और सशक्त राज्य के रूप में राष्ट्र के मानचित्र पर स्थापित कर हम राज्य की जनता की आशा और विश्वास पर खरे उतरेंगे।

3. इस सदन में पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013–14 बजट अनुमानों के अनुसार, 1 हजार 25 करोड़ 86 लाख रुपये का Revenue Surplus और 13 हजार 19 करोड़ 86 लाख रुपये का Fiscal Deficit अनुमानित किया था। Revenus Surplus और Fiscal Deficit का अनुमान जानबूझ कर त्रुटिपूर्ण रूप से किया गया था। उदाहरण के लिए, सामाजिक पेंशन योजनाओं के तहत बजट अनुमान मात्र 710 करोड़ रुपये रखा गया था। बजट प्रस्तुत करते समय घोषणा की गई कि 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जायेगा। यदि 1500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भार का प्रावधान बजट में ही कर दिया जाता,

तो Revenue Surplus 1 हजार 25 करोड़ रुपये के स्थान पर 475 करोड़ रुपये के Revenue Deficit में बदल जाता। यही नहीं, वर्ष के दौरान पेंशन हेतु 1 हजार 465 करोड़ रुपये के Additional authorization किये गये यानि कुल प्रावधान 2 हजार 175 करोड़ रुपये रखा गया। वास्तव में पेंशन योजना पर व्यय 2 हजार 540 करोड़ रुपये होगा जिसका प्रावधान अब हमने संशोधित अनुमानों में किया है। इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में होने वाले चुनावों को मध्यनज़र रखते हुए गत राज्य सरकार ने अनेक योजनाओं की आनन फानन में घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूर्व सरकार द्वारा सितम्बर माह तक लगभग 14 हजार करोड़ रुपये का Additional authorization बजट से परे जाकर किया। इन घोषणाओं और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप इस वर्ष

Revenue Surplus का Revenue Deficit में बदलना निश्चित था और Fiscal Deficit भी 3 प्रतिशत की सीमा से कहीं अधिक पहुंचना ही था।

4. हमने गत 2 माह में बेकाबू होते जा रहे Revenue और Fiscal Deficit को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। हम कुछ सीमा तक Fiscal Deficit और Revenue Deficit को नियंत्रित करने में सफल भी हुए हैं। सदन के समक्ष वर्ष 2013–14 हेतु अब प्रस्तुत संशोधित अनुमानों के अनुसार Revenue Deficit 2 हजार 505 करोड़ 15 लाख रुपये अनुमानित है और Fiscal Deficit 18 हजार 301 करोड़ 27 लाख रुपये अनुमानित है। इस प्रकार राज्य दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस वित्तीय वर्ष में Revenue Deficit में रहेगा व Fiscal Deficit के भी GSDP के 3.56 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। निश्चित ही ये परिणाम

FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण राज्य को National Small Savings Fund (NSSF) ऋणों पर ब्याज दरों में मिलने वाली 172 करोड़ रुपये की राहत से वंचित रहना पड़ेगा।

5. माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व सरकार द्वारा इस वर्ष की योजना का आकार 40 हजार 500 करोड़ रुपये निर्धारित किया था। इस स्तर की योजना को वित्त पोषित करने के लिये केन्द्रीय करों से 20 हजार 361 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान किया गया था। ये अनुमान अपने आप में ही अव्यवहारिक थे। पिछले कुछ महीनों से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के हिस्से में कटौती की जा रही है जिसके कारण इस वर्ष हमें कम से कम 1 हजार 200 करोड़ रुपये कम प्राप्त

होंगे। इसके बावजूद भी हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष की संशोधित योजना को 42 हजार 498 करोड़ 81 लाख रुपये तक बढ़ाया गया है।

6. अब मैं, वर्ष 2014–15 के बजट अनुमानों के मोटे तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ।

7. वर्ष 2014–15 में 1 लाख 12 हजार 955 करोड़ 6 लाख रुपये का कुल व्यय अनुमानित किया गया है। इन बजट अनुमानों में Revenue Expenditure 90 हजार 752 करोड़ 23 लाख रुपये और Revenue Receipts 91 हजार 483 करोड़ 98 लाख रुपये अनुमानित की गई हैं। इस प्रकार पुनः राज्य को Revenue Surplus की तरफ लाने के लिए राजस्व खाते में 731 करोड़ 75 लाख रुपये का Revenue Surplus अनुमानित किया गया है। राज्य का Fiscal Deficit

रुपये 16 हजार 355 करोड़ होना अनुमानित किया गया है जो कि राज्य की अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के 2.86 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हम राज्य को पुनः GSDP के 3 प्रतिशत से कम Fiscal Deficit में लाने के लिए संकल्पित हैं। राज्य का Debt-GSDP ratio 25.73 प्रतिशत रहना अनुमानित है। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि राज्य आगामी वर्ष में FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा कर सकेगा।

8. केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वर्ष 2014–15 के लिए दिनांक 17 फरवरी, 2014 को लोकसभा में लेखानुदान की मांग प्रस्तुत की गई है। इस तिथि से पूर्व ही राज्य सरकार के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने के कारण केन्द्र सरकार से आगामी वर्ष में राज्य को मिलने वाले करों के भाग व अन्य अनुदान राशियों की विगत का आकलन राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर ही किया गया है। इसी

प्रकार Centrally Sponsored Schemes के संबंध में अगले वर्ष मिलने वाली राशियों की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। न ही योजना आयोग द्वारा अभी तक केन्द्रीय सहायता योजनाओं की पूर्ति हेतु संसाधनों की राशि निर्धारित की गई है।

9. हमारी सरकार द्वारा आगामी वर्ष 2014–15 का योजना व्यय 46 हजार 989 करोड़ 33 लाख रुपये अनुमानित किया गया है। राज्य सरकार वर्ष 2014–15 में राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी योजनाएं लाएगी जिससे जनता का सीधा लाभ हो। सामाजिक और आर्थिक आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करना हमारी प्राथमिकता है। सौर ऊर्जा से पांच वर्ष में 25 हजार मेगावाट बिजली पैदा करना, राज्य के पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों को सड़कों के एक नेटवर्क (East-West Corridor) सहित राज्य

में लगभग 20 हजार किलोमीटर के राज्य मार्ग और (Major District Roads) को मेगा हाईवेज़ के स्तर तक upgrade करने और राज्य के 20 हजार से अधिक under-served और problematic गांवों में अच्छे पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में गरीब व अशक्त परिवारों को सभी व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ एक साथ भामाशाह योजना के माध्यम से कराया जाएगा। हमारी प्राथमिकताओं और जन आकांक्षाओं के अनुकूल योजनाओं हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य की परिवर्तित योजना वर्ष 2014—15 के परिवर्तित बजट अनुमानों के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

10. वर्ष 2014—15 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदानों की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। आगामी

लोकसभा चुनावों के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च, 2014 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है, अतः हम वित्तीय वर्ष 2014–15 के पहले चार महीनों के लिए, यथा 31 जुलाई, 2014 तक व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस लेखानुदान में मांग संख्या 7–निर्वाचन, मांग संख्या 27–पेयजल और मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है क्योंकि इन मदों में इन्ही महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है और इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान की अवधि यथा 31 जुलाई, 2014 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिये जाऐंगे।

मैं लेखानुदान प्रस्तावों को स्वीकृत करने के अनुरोध के साथ, माननीय सदन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ।